

स्थानीय निकायों हेतु उपार्जन लेखा : निर्वाचित प्रतिनिधि तथा हितधारक

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
सभी अधिकार सुरक्षित

इस पुस्तिका का कोई भी भाग बिना प्रकाशक की पूर्वलिखित अनुमति के उल्लेखित, पुनः प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत, या संचारित, अन्य रूप, या दूसरे किसी भी साधन, ईलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, रिकार्डिंग या अन्यथा नहीं किया जा सकता है।

प्रथम हिन्दी संस्करण : अगस्त 2009

ई मेल : caslb@icai.org

वैबसाईट : <http://www.icai.org>

प्रकाशित द्वारा :
सीए. केशव दत्त,
सचिव,
स्थानीय निकायों हेतु लेखा मानक समिति
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान,
'आई सी ए आई भवन',
इन्द्रप्रस्थ मार्ग,
नई दिल्ली-110 002, भारत

मुद्रित द्वारा :
परफेक्ट इम्प्रेशन (प्रा.) लि.
दूरभाष : + 91-11-2460 2233/77

अध्यक्षीय सन्देश

इस पुस्तिका का अंग्रेजी संस्करण, स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अन्य हितधारकों के लिए उपार्जन लेखा प्रणाली विषय पर संस्थान द्वारा जनवरी 30, 2009 को प्रकाशित किया जा चुका है।

चूंकि भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य किया जाता है तथा वहाँ पर आम लोगों के संचार एवं संवाद का माध्यम मुख्यतः क्षेत्रीय भाषाएं ही हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए यह महसूस किया गया कि इस पुस्तिका का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को मध्यनजर रखते हुए संस्थान की स्थानीय निकायों हेतु लेखा मानक समिति ने पुस्तिका का हिन्दी रूपान्तरण किया है।

इस पुस्तिका में सरल भाषा का प्रयोग किया है ताकि इसकी उपयोगिता उन लोगों तक पहुँच सके, जिनको ध्यान में रखकर इसे अनुवादित किया गया है। इस पुस्तिका को हिन्दी में अनुवादित करने के लिए मैं स्थानीय निकायों हेतु लेखा मानक समिति के चेयरमैन, सीए. जयन्त गोखले एवं सचिव, सीए. केशव दत्त द्वारा किये गये प्रत्यनों की सराहना करता हूँ।

यह उल्लेखनीय है कि पुस्तिका के अंग्रेजी संस्करण को उत्तरी-पूर्वीय राज्यों सहित देश के विभिन्न राज्यों द्वारा काफी सराहा गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुस्तिका का हिन्दी संस्करण हिन्दी भाषी राज्यों के स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों व अन्य सम्बन्धित के लिए सहायक होगी।

नई दिल्ली
अगस्त 30, 2009

सीए. उत्तम प्रकाश अग्रवाल
अध्यक्ष

प्राक्कथन

भारत में शासन प्रणाली के कई संघटक हैं, जिनमें से एक स्थानीय निकाय है जैसे कि नगर निगम, नगरपालिकाएँ, पंचायतें आदि। बदलते परिवेश में स्थानीय निकायों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जवाबदेही और पारदर्शिता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय निकाय द्वारा उचित वित्तीय रिपोर्टिंग शायद अत्याधिक महत्वपूर्ण साधन है। स्थानीय निकाय वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पारम्परिक रूप से लेखा के नकदी आधार का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि उनके बजट, जो कि नकदी आधार पर तैयार किए जाते हैं, वित्तीय नियंत्रण का प्रमुख साधन रहे हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उनकी रिपोर्टिंग प्रणाली के संबंध में स्थानीय निकायों की रूपावली में आमूल परिवर्तन आया है। कुछ स्थानीय निकायों ने लेखा के विद्यमान नकदी आधार को छोड़कर विभिन्न रूपों में लेखा की उपार्जन (एक्रुअल) प्रणाली को अपनाने के वास्तविक प्रयास किए हैं। ऐसे निकायों द्वारा अधिक जवाबदेह और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की दिशा में उठाया गया कदम स्वागत योग्य है। भारत सरकार, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे. एन. एन. यू. आर. एम.) ने भारत में स्थानीय निकायों में लेखा संबंधी सुधार लाने के लिए अनेक पहल की हैं।

भारत में स्थानीय निकाय, विशेषकर लेखा सम्बन्धी सुधारों को देखते हुए, तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे हैं और अधिक संख्या में ऐसे निकाय स्थानीय निकायों की लेखा संबंधी ऐसी प्रणालियों और व्यवहारों को अपनाने में—जो गौरतलब रूप से वित्तीय पारदर्शिता के स्तरों को बढ़ाए और उन सभी को अपनी वित्तीय स्थिति का स्पष्ट चित्र प्रदान करे। 'स्थानीय निकायों हेतु उपार्जन (एक्रुअल) लेखा : निर्वाचित प्रतिनिधि और हितधारक' नामक यह पुस्तिका उपार्जन (एक्रुअल) लेखा के लाभों के बारे में निर्वाचित प्रतिनिधियों और हितधारियों को आरंभिक जानकारी प्रदान करती है। इस पुस्तिका को परिकल्पित तथा व्यावहारिक रूप देने के लिए मैं सीए. जयंत गोखले और तकनीकी निदेशालय का धन्यवाद करता हूँ।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह पुस्तिका भारत में स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और हितधारियों तथा सम्बन्धित अन्यो के लिए भी अत्यंत सहायक होगी।

नई दिल्ली
30 जनवरी, 2009

सीए. वेद जैन
अध्यक्ष

प्रस्तावना

आर्थिक शक्ति बनने की दिशा की ओर अग्रसर भारत देश के नागरिकों को सर्वोत्तम अधोसंरचना उपलब्ध कराने में स्थानीय निकाय अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे. एन. एन. यू. आर. एम.) ने शहरी सुधारों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है और राज्यों व नगर पालिकाओं के योगदान को जोड़ने से यह राशि राज्यों व स्थानीय निकायों के योगदान के बाद सात वर्षों के अंदर लगभग 1,26,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। लेखा सम्बन्धी सुधार और उपार्जन (एक्रुअल) लेखा प्रणाली को अपनाना सुधार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेखा संबंधी सुधारों का उद्देश्य नागरिकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रशासकों, निवेशकों, लेनदारों, कार्यपालकों, विधान-मंडलों, राज्य लेखा-परीक्षा विभागों, और राज्यों के शहरी विकास और पंचायती राज विभागों जैसे भिन्न प्रयोक्ताओं को समय पर व संगठित रूप से वित्तीय जानकारी प्रदान करना है। स्थानीय निकायों हेतु लेखा मानक समिति ने स्थानीय निकायों में लेखा संबंधी सुधार प्रक्रिया के लाभों के बारे में विभिन्न हितधारियों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता को पहचाना है।

इस पुस्तिका का उद्देश्य उन व्यक्तियों में उपार्जन (एक्रुअल) लेखा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करना है जिन्हें भारत में स्थानीय निकायों के शासन का दायित्व सौंपा गया है। यह लेखा की दो प्रणालियों : पारम्परिक नकदी लेखा प्रणाली और आधुनिक उपार्जन (एक्रुअल) लेखा प्रणाली, की विशेषताओं और स्थानीय निकाय की आय, व्यय, आस्तियों और देनदारियों को प्रभावित करने के तरीके को प्रकट करती है। यह पुस्तिका इस बात पर भी चर्चा करती है कि दोहरी प्रविष्टि उपार्जन (एक्रुअल) लेखा प्रणाली स्थानीय निकायों के लिए किस प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। उपार्जन (एक्रुअल) लेखांकन प्रणाली तथा इसके प्रयोग के संबंध में व्याप्त जानकारी के अंतर को कम करने के लिए कुछ गलत धारणाओं को भी स्पष्ट किया गया है। आशा है कि यह पुस्तिका, वित्तीय सुधारों में उपार्जन (एक्रुअल) लेखा की भूमिका का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करेगी और इस बारे में सभी आशंकाओं का निवारण करेगी। इस संभावना

को पूर्णतः प्राप्त करने में उक्त पुस्तिका को जल्द ही भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी किया जाएगा ताकि इसका लाभ निचले प्रशासकों, कारपोरेटों और पार्षदों तथा आम नागरिकों द्वारा उठाया जा सके। पुस्तिका का प्रारूप तैयार करने में, मैं इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के तकनीकी निदेशक डा० अविनाश चन्द्र और स्थानीय निकायों हेतु लेखा मानक समिति के सचिव सीए. केशव दत्त द्वारा किए गए प्रयासों की निष्ठापूर्वक सराहना करता हूँ।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यह पुस्तिका भारत में स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और हितधारियों तथा सम्बन्धित अन्यो के लिए भी अत्यंत सहायक होगी।

नई दिल्ली
अगस्त 30, 2009

सीए. जयंत गोखले
चेयरमैन
स्थानीय निकायों हेतु
लेखा मानक समिति

विषय वस्तु

परिचय	1
प्रयोक्ता समूह	1
लेखा आधार	3
• नकदी लेखा	3
• उपार्जन (एक्रुअल) लेखा	4
• लेखा के नकदी आधार और उपार्जन (एक्रुअल) आधार के बीच अंतर	4
उपार्जन (एक्रुअल) लेखा का विशेष प्रभाव	10
उपार्जन (एक्रुअल) लेखा के लाभ	11
स्थानीय निकायों में उपार्जन (एक्रुअल) लेखा के बारे में मिथक तथा वास्तविकताएँ	12
स्थानीय निकायों हेतु लेखा मानक समिति के बारे में	14
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया) के बारे में	15

परिचय

- एक विशिष्ट क्षेत्र के नागरिकों से प्राप्त किए जाने वाले सम्पत्ति कर की राशि कितनी है?
- एक स्थानीय निकाय के नियंत्रण में आने वाली भूमि, इमारतों, सड़कों, पुलों आदि की कुल कितनी कीमत है?
- क्षेत्र के नागरिकों को जल की आपूर्ति करने की लागत कितनी है?
- क्षेत्र के नागरिकों को जल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनुदान की राशि कितनी है?
- स्थानीय निकाय की अपने लेनदारों के प्रति कितनी देनदारी हैं ?
- स्थानीय निकाय की वित्तीय प्रदर्शन की दक्षता का स्तर क्या है और इसे किस प्रकार सुधारा जा सकता है?

उपरोक्त सभी प्रश्न और ऐसे ही कुछ और प्रश्न आम लोगों, करदाताओं, मतदाताओं, सेवा प्राप्तकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और पक्षसमर्थक समूहों द्वारा, विशेष रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण, पूछे जा सकते हैं, चूंकि यह अधिनियम लोगों को किसी भी मामले के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर नकदी आधार की लेखा प्रणाली के अंतर्गत सुगमता से उपलब्ध नहीं होते। यदि कोई नकदी लेखा संबंधी रिकार्डों और आँकड़ों से परे जाने का प्रयास भी करे तो वह केवल निकटतम अनुमानित उत्तर ही प्रदान कर सकते हैं, जिन्हें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षक, और सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकेगा।

दोहरी प्रविष्टि पर आधारित उपार्जन (एक्रुअल) लेखा प्रणाली ही एकमात्र ऐसी प्रणाली है जो उपरोक्त प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर प्रदान करने में मदद करती है। यह उच्च स्तरीय पारदर्शिता और प्रयोक्ता समूहों के प्रति जवाबदेही जैसी विशेषताओं वाली वित्तीय जानकारी भी प्रदान करती है।

चूंकि इन स्थानीय निकायों का नियंत्रण सामान्यतः उन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जिन्हें अपने क्षेत्र के नागरिकों की अपेक्षाओं का ध्यान रखना होता है, हमें उनके प्रयोग के लिए उपार्जन (एक्रुअल) लेखा पर एक पुस्तिका बनाने की आवश्यकता महसूस हुई।

उपयोगकर्ता समूह और उनकी जानकारी संबंधी आवश्यकताएँ

स्थानीय निकायों की वित्तीय जानकारी के प्रमुख उपयोगकर्ता हैं :

(i) **नागरिक** : इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- करदाता
- मतदाता
- सेवा प्राप्तकर्ता
- पक्ष-समर्थक समूह के सदस्य
- गैर-सरकारी संगठनों के आयोजक
- सार्वजनिक वित्त शोधकर्ता
- उधार देने वाले अभिकरण
- निवेशक

उपरोक्त सभी उपयोगकर्ता प्रदान की गई सेवाओं के स्तर में आई वृद्धि या गिरावट के संकेतकों और भविष्य में कर भार के रूप में स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति और उसके परिचालन परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में रूचि रखते हैं।

(ii) **निर्वाचित प्रतिनिधि** : निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह पता लगाना होता है कि सेवाएँ प्रदान करने के लिए कितना धन उपलब्ध है और सीमित निधि के साथ अधिकतम सेवाएँ किस प्रकार प्रदान की जाएँ ताकि करों का स्तर कम रहे। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च की गई धन राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है।

(iii) **अनुदान/निधि को मंजूरी देने/जारी करने और उनके उपयोग पर निगरानी रखने वाले सरकारी प्राधिकरण**

(iv) **कार्यपालक** : कार्यपालक को वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन का कठिन कार्य करना होता है। उन्हें बजट में दिए गए विधायी प्रयोजनों के निर्देशों, निर्वाचित प्रतिनिधियों की राजनीतिक आवश्यकताओं, लेनदारों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवेकशीलता, वित्तीय अनुशासन के पालन और

अतिरिक्त वित्त के साथ कौन सी नई परियोजनाएँ प्रारंभ की जा सकती है, आदि के बीच में संतुलन स्थापित करना होता है।

(v) **लेनदार** : लेनदारों का उद्देश्य संसाधनों का विवेकशील प्रबंधन सुनिश्चित करना है ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके।

(vi) **राज्य लेखा परीक्षा** : राज्य लेखा परीक्षा एक सरकारी विभाग है जिसे यह सुनिश्चित करना होता है कि सम्बन्धित विभागों द्वारा सांविधिक प्रावधानों, संविदात्मक दायित्वों व ऋण अनुबन्धों का अनुपालन किया गया है व सभी वित्तीय संव्यवहारों को संगत नियमों और विनियमों के अनुसार किया है। विभाग यह भी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि वित्तीय रिपोर्टिंग संस्था की वित्तीय प्रदर्शन स्थिति का यथार्थ व निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

(vii) **राज्य नगरीय विकास/पंचायत राज विभाग** : ये विभाग राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कुछ मामलों में सामान्य और विशेष प्रयोजनों हेतु अनुदान के माध्यम से स्थानीय निकायों के संसाधनों का करीब 90 प्रतिशत भाग प्रदान करते हैं। इन विभागों को आगामी वर्षों के लिए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के मूल्यांकन हेतु स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार को यह जानने की आवश्यकता भी होती है कि शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थाएँ अपने कार्य वित्तीय विवेकशीलता के साथ और स्वीकृत बजट द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहकर करते हैं या नहीं।

लेखा आधार

नकदी आधार और उपार्जन (एक्रुअल) आधार लेखा की दो प्रसिद्ध पद्धतियाँ हैं। कर से प्राप्त आय पर अपनी निर्भरता के साथ स्थानीय निकाय पारम्परिक रूप से नकदी आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति पर निर्भर रहे हैं।

(क) नकदी लेखा

स्थानीय निकायों द्वारा नकदी आधारित लेखा को अपनाने का मुख्य कारण सरकार में वित्तीय नियंत्रण के मुख्य साधनों के रूप में प्रमुख रूप में बजट है। सरकार में बजट एक औपचारिक दस्तावेज है जो उन उद्देश्यों को दर्शाता है जिनके चलते एक अवधि के दौरान व्यय किया जाता है और उन स्रोतों को व्यक्त करता है जिनसे इस व्यय की पूर्ति हेतु निधि प्राप्त की जाती है। लेखा का नकदी आधार बजट की तुलना में रखे गए लक्ष्यों में वास्तविक प्रदर्शन की तुलना को

सुविधाजनक बनाने के लिए, विभिन्न बजट शीर्षों के अंतर्गत दी गई वास्तविक प्राप्तियों और भुगतानों को मापता है।

नकदी आधारित विधि में आय को नकदी प्राप्त होने पर माना जाता है और व्यय को नकदी के भुगतान पर माना जाता है, नकदी प्राप्तियों और भुगतानों का मिलान लेखा-अवधि के दौरान प्रचालन संबंधी परिणामों को ज्ञात करने में सहायक होता है। यह विधि प्रयोग में सरल है, लेकिन अधिकतर स्थितियों में यह प्रस्तुत अवधि में प्राप्त की गई आय के प्रति किये गये सभी व्ययों का पूर्णतः मिलान नहीं करती। उदाहरण के लिए, उपकरण या एक इमारत का क्रय एक समयावधि के दौरान मूल्यहास नहीं होता बल्कि क्रय के समय ही पूर्णतः खर्च दर्शा दिया जाता है।

लेखा का नकदी आधार वित्तीय रिपोर्टिंग के अधिकतर उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि नकदी प्राप्तियों और नकदी भुगतानों का समय, राजस्व के अर्जन या व्ययों के होने से मेल नहीं खा पाता। इसके अतिरिक्त, लेखा के नकदी आधार पर आधारित प्रदर्शन के मापन में नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के समय में हुई भिन्नता द्वारा हेरा-फेरी की गुंजाइश है। उदाहरण के लिए, कुछ बिलों के भुगतान का कुछ दिनों के लिए स्थगन बजटीय घाटे को छुपा सकता है। लेखा के नकदी आधार की एक अन्य प्रमुख कमी यह है कि पूंजीगत लेखा और राजस्व लेखा में दी गई प्राप्तियों या भुगतानों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता। उदाहरणतः सड़कों, जल वितरण प्रणाली, पुलों आदि जैसी अधोसंरचना सुविधाओं के निर्माण पर किए गए व्यय और वेतन, किराया आदि जैसी नियमित मदों पर किए गए व्यय के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता। इसी प्रकार से, इमारत में ऐसे प्रमुख परिवर्तन करने हेतु-जिसके परिणामस्वरूप इमारत की उम्र बढ़े- किए गए अच्छे-खासे व्यय को भी सामान्य मरम्मत और अनुरक्षण संबंधी कार्य पर किए गए किसी राजस्व संबंधी व्यय से पृथक नहीं माना जाता। इसी प्रकार, वापसी योग्य जमा व प्रदान की गई सेवा प्रभारों में कोई अन्तर नहीं किया जाता है।

लेखा के नकदी आधार की प्रमुख कमियाँ हैं :

- आय तथा व्यय का गलत मापन
- परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए कोई विवरण न होना

इन कमियों के कारण कई सरकारों और सरकारी निकायों ने उपार्जन (एक्रुअल) लेखा प्रणाली की ओर रूख किया है।

(ख) उपार्जन (एक्रुअल) लेखा

उपार्जन (एक्रुअल) लेखा, वित्तीय संव्यवहारों को तब मानता है जब वे घटित होते हैं न कि तब जब नकदी प्राप्त होती है या उसका भुगतान किया जाता है। उपार्जन (एक्रुअल) विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक निश्चित अवधि के दौरान अर्जित सभी आयों को उन आयों को अर्जित करने के लिए किये गये व्ययों के साथ मिलाया जाता है। अन्य शब्दों में, आयों को उस अवधि में रिकार्ड किया जाता है जिस अवधि में उनको अर्जित किया जाता है और व्ययों को उन आयों को अर्जन करने के लिए उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं को माप कर माना जाता है; और स्थायी आस्तियों से सम्बंधित बहुवर्षीय लाभों को उस समय अथवा उन समयों से मिलाया जाता है जिस अवधि में उनका प्रयोग किये जाने की आशा हो।

उपार्जन (एक्रुअल) विधि शुद्ध आय का बेहतर मापन प्रदान करती है क्योंकि यह हो चुके व्ययों को निश्चित अवधि की अर्जित आयों के साथ मिलान करती है और यह उस अवधि में आय को दर्शाती है जिस अवधि से वह संबंधित है अर्थात् जिस अवधि में उनका अर्जन किया गया है। इस प्रकार, शुद्ध आय को स्पष्टतः अर्जित आयों और उन आयों के अर्जन करने के लिए हो चुके व्ययों के बीच के अंतर के रूप में अर्थात् प्राप्त परिणामों और उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों के बीच के अंतर के रूप में दर्शाया जाता है। चूंकि उपार्जन (एक्रुअल) लेखा नकदी आधारित लेखा की तुलना में अधिक पूर्ण और उपयोगी जानकारी प्रदान करता है, अतः अधिकतर संगठन अपने निर्णय लेने और वित्तीय रिपोर्टिंग को समर्थन देते हुए इसी प्रणाली का प्रयोग करते हैं।

(ग) लेखा के नकदी और उपार्जन (एक्रुअल) आधारों के बीच अंतर

लेखा के उपार्जन (एक्रुअल) आधार और नकदी आधार के बीच का प्रमुख अंतर राजस्व, व्यय, लाभ और हानि को मानने के समय में है। यह संभव है कि एक विशेष अवधि के दौरान नकद प्राप्तियाँ मुख्यतः पिछली अवधियों में उपक्रम की गतिविधियों के प्रभावों को दर्शाती है जबकि कई नकदी भुगतान भावी अवधियों में अपेक्षित गतिविधियों और प्रयासों से सम्बंधित हो सकते हैं। इस प्रकार अल्प अवधि के लिए एक उपक्रम की नकद प्राप्तियों और नकद भुगतानों को दर्शाने वाला लेखा यह नहीं दर्शा सकता कि प्राप्त किए गए नकदी में से कितनी नकदी निवेश का प्रतिफल है और निवेश पर कितना प्रतिफल प्राप्त हुआ है और यह नहीं दर्शा सकता कि क्या उपक्रम सफल है या उपक्रम किस सीमा तक सफल या असफल है।

क ख ग स्थानीय निकाय का निम्नलिखित उदाहरण शुद्ध आय ज्ञात करने की नकद और उपार्जन (एक्रुअल) आधारित विधियों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है :

उदाहरण 1

क ख ग स्थानीय निकाय ने अगस्त माह में सेवा प्रदान की जिसके लिए इसने 1,000 रुपए का शुल्क लिया। इसने अपनी सेवाओं के लिए शुल्कों को दो तिथियों क्रमशः 14 अगस्त को 600 रु० और 10 सितम्बर को 400 रु० प्राप्त किये। 31 अगस्त को 550 रु० की मजदूरी और वेतन (केवल व्यय) का भुगतान किया गया । सितम्बर के दौरान कोई भी सेवा प्रदान नहीं की गई।

लेखा आधार	नकद आधार		उपार्जन (एक्रुअल) आधार	
	अगस्त	सितम्बर	अगस्त	सितम्बर
राजस्व	600 रु०	400 रु०	1,000 रु०	0 रु०
व्यय	550 रु०	0 रु०	550 रु०	0 रु०
शुद्ध आय	50 रु०	400 रु०	450 रु०	0 रु०

नकद आधारित विधि का प्रयोग करते हुए, आय को उन महीनों में रिकार्ड किया जाता है जिन महीनों में नकदी को प्राप्त किया जाता है और व्ययों को उस माह में रिकार्ड किया जाता है जिस माह में नकदी का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार, अगस्त माह की शुद्ध आय 50 रु० और सितम्बर माह के लिए 400 रु० बैठती है यद्यपि सितम्बर माह में कोई कार्य नहीं किया गया था। समायोजन के बाद उपार्जन (एक्रुअल) आधार पर एक अवधि में अर्जित सभी आयों को अर्जित करने के लिए उपगत सभी व्ययों से मिलान करता है। यह तथ्य दर्शाते हुए कि सभी सेवाएँ अगस्त में प्रदान की गई थी, अब शुद्ध आय अगस्त माह के लिए 450 रु० और सितम्बर माह के लिए 0 रु० बैठती है।

उदाहरण 2

क ख ग नामक स्थानीय निकाय ने वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए आय तथा व्यय के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की।

	रु०
वर्ष में प्राप्त सम्पत्ति कर से आय	1,20,000
अग्रिम प्राप्त सम्पत्ति कर	15,000
अर्जित किंतु अप्राप्त सम्पत्ति कर	12,000
वर्ष में स्कूली शिक्षा हेतु किये गये व्यय	80,000
स्कूली शिक्षा हेतु किये गये अग्रिम व्यय	20,000
स्कूली शिक्षा हेतु वहन किये गये किंतु भुगतान न किये गये व्यय	10,000

(क) नकदी आधार (ख) उपार्जन (एक्रुअल) आधार के अंतर्गत क ख ग स्थानीय निकाय के आय तथा व्यय लेखा इस प्रकार होंगे :

(क) नकदी आधार

	रु०	रु०
आय :		
वर्ष में प्राप्त सम्पत्ति करों से आय	1,20,000	
अग्रिम प्राप्त सम्पत्ति कर	15,000	
कुल आय (क)		1,35,000
व्यय :		
वर्ष में स्कूली शिक्षा हेतु किये गये व्यय	80,000	
स्कूली शिक्षा हेतु अग्रिम किये गये अग्रिम व्यय	20,000	
कुल व्यय (ख)		1,00,000
शुद्ध आय (क-ख)		35,000

(ख) उपार्जन (एक्रुअल) आधार

	रु०	रु०
आय:		
वर्ष में प्राप्त सम्पत्ति कर से प्राप्त आय	1,20,000	
अर्जित किंतु अप्राप्त सम्पत्ति कर	12,000	
अग्रिम प्राप्त सम्पत्ति कर	(15,000)	
कुल आय (क)		1,17,000

व्यय :		
वर्ष में स्कूली शिक्षा हेतु किये गये व्यय	80,000	
स्कूली शिक्षा हेतु वहन किये गये लेकिन अदत्त (भुगतान न किये गये) व्यय	10,000	
स्कूली शिक्षा हेतु अग्रिम भुगतान किये गये व्यय	(20,000)	
कुल व्यय (ख)		70,000
शुद्ध आय (क - ख)		47,000

उपरोक्त उदाहरण लेखा के दो आधारों के बीच का अंतर स्पष्टतः प्रकट करता है। लेखा के उपार्जन (एक्रुअल) आधार पर 47,000 रु० की शुद्ध आय वर्ष में 'क ख ग' स्थानीय निकाय की सही आय को दर्शाती है जबकि नकदी आधार पर 35,000 रु० की शुद्ध आय वार्षिक प्राप्तियों व भुगतानों का मात्र अन्तर है। इस प्रकार, उपार्जन (एक्रुअल) लेखा आधार, लेखा संव्यवहारों को मापने की एक वैज्ञानिक विधि है जोकि विश्व स्तर पर सरकारों द्वारा अपने वित्तीय संव्यवहारों के लिए प्रयोग में लाई जा रही है।

लेखा आधारों का तुलनात्मक विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :

लेखा के नकदी व उपार्जन (एक्रुअल) आधारों में अन्तर

घटक	नकद आधार	उपार्जन (एक्रुअल) आधार
आय	जब रोकड़ प्राप्त किया जाता है। उदाहरण : <ul style="list-style-type: none"> • सम्पत्ति करों के प्राप्त होने पर • शुल्कों और जुर्मानों के प्राप्त होने पर • अनुदान संबंधी धन के बैंक के खाते में हस्तांतरण पर 	जब आय अर्जित की जाती है। उदाहरण : <ul style="list-style-type: none"> • सम्पत्ति करों के प्राप्य होने पर-मांग पत्र के जारी हो जाने पर • अनुदान हेतु स्वीकृति पत्र की प्राप्ति पर • अन्य अभिकरणों के साथ राजस्व सहभागिता अनुबंध की स्थिति में जैसे पब्लिक यूटीलिटीज़ के सम्बन्ध में, जब उस संस्था ने उस राजस्व को अर्जित किया हो जिसके एक भाग को यू. एल. बी./पी. आर. आई. के साथ बाँटा जाना हो।

घटक	नकद आधार	उपार्जन (एकूअल) आधार
व्यय	जब रोकड़ का भुगतान कर दिया गया हो। उदाहरण : • जब वेतन का भुगतान कर दिया गया हो। • जब पूर्तिकर्ताओं के बिलों का भुगतान कर दिया गया हो।	जब व्यय को वहन किया गया हो और एक देनदारी उत्पन्न हो जाए। उदाहरण : • जब माह के अंत में वेतन कर्मचारियों के प्रति देय हो जाए। • जब पूर्ति प्राप्त करने पर पूर्तिकर्ता के प्रति भुगतान देय हो जाए।

उपार्जन (एकूअल) आधार के अंतर्गत राजस्व/व्यय अभिज्ञान के संबंध में नकदी प्राप्तियों/भुगतानों को नीचे और अधिक स्पष्ट किया गया है :

रोकड़ प्राप्ति बनाम राजस्व अभिज्ञान

रोकड़ प्राप्ति	पूर्व अवधि	वर्तमान अवधि	उत्तरगामी अवधि
आय के अर्जन के साथ-साथ वर्तमान अवधि में प्राप्त रोकड़		1. अर्जित आय 2. रोकड़ में वृद्धि	
आय के अर्जन से पहले, पूर्व अवधि में प्राप्त रोकड़	1. वस्तुओं को प्रदान करने या सेवाएँ प्रदान करने के दायित्व में वृद्धि 2. रोकड़ में वृद्धि	1. अर्जित आय 2. वस्तुओं या सेवाएँ प्रदान करने के दायित्व में कमी	
आय के अर्जन के बाद, उत्तरगामी अवधि में प्राप्त रोकड़		1. अर्जित आय 2. देनदारों में बढ़ोतरी	1. रोकड़ में वृद्धि 2. देनदारों में कमी

रोकड़ भुगतान बनाम व्यय अभिज्ञान

रोकड़ भुगतान	पूर्व अवधि	वर्तमान अवधि	उत्तरगामी अवधि
आय अर्जित करने के साथ-साथ संसाधनों का प्रयोग करते हुए वर्तमान अवधि में भुगतान की गई रोकड़।		1. व्यय 2. रोकड़ में कमी	
आय अर्जित करने के लिए संसाधनों का प्रयोग करने से पहले पूर्व अवधि में भुगतान की गई रोकड़।	1. रोकड़ में कमी 2. पूर्वभुगतान में वृद्धि	1. व्यय 2. पूर्वभुगतान में कमी	
आय अर्जित करने के लिए संसाधनों का प्रयोग करने के बाद उत्तरगामी अवधि में भुगतान की गई रोकड़		1. व्यय 2. प्रयुक्त संसाधनों हेतु भुगतान के प्रति-देनदारी में वृद्धि	1. रोकड़ में कमी 2. प्रयुक्त संसाधनों हेतु भुगतान के प्रति-देनदारी में कमी

उपार्जन (एक्रुअल) लेखा का विशेष प्रभाव

उपार्जन (एक्रुअल) लेखा का प्रभाव आस्तियों, देनदारियों, आयों और व्ययों पर पड़ता है, लेकिन प्रमुख प्रभाव निम्न पर पड़ता है :

1. स्थिर आस्तियाँ

नकदी लेखा का प्रयोग करते हुए स्थानीय निकाय की आस्तियों जैसे कि इमारतें, वाहन और उपकरण आदि को स्थानीय निकाय के तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में नहीं दर्शाया जाता। आस्ति की क्रय-कीमत को क्रय के वर्ष में पूर्णतः खर्च किया जाता है और इसीलिए इस व्यवहार या सौदे का वार्षिक बजटीय अधिशेष (बैलेंस) पर तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। उपार्जन (एक्रुअल) विधि में, इन पूंजीगत व्ययों को स्थानीय निकाय के तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में आस्तियों के रूप में रिकार्ड किया जाता है। आस्ति प्रयोग करने की वार्षिक लागत को आस्तियों के मूल्य पर अनुमानित वार्षिक मूल्यहास एवं संचालन और रखरखाव के खर्चों को दर्शाया जाता है।

2. देनदारियाँ

नकदी लेखा प्रणाली में देनदारियों और प्रावधानों, जैसे कि बकाया व्यय लेनदारों, कर-वापसी (रिफण्ड), अग्रिम रूप से प्राप्त आयों और कार्य के ठेकेदारों के अदत्त बिलों को स्थानीय निकाय के तुलन-पत्र में नहीं दर्शाया जाता। उपार्जन (एक्रुअल) लेखा के तुलन-पत्र में देनदारियों की अधिक विस्तृत सूची शामिल होती हैं। इसमें बकाया व्यय, लेनदार, कर-वापसी हेतु प्रावधान, अग्रिम रूप से प्राप्त आय, अन्य पक्षकारों के प्रति दावों से संबंधित संभावित देनदारियाँ जो कि अनुमानित की जा सके उनका भुगतान सम्बन्धित हो और, कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभों के लिए प्रावधानों के कारण बढ़ी हुई देनदारियाँ आदि शामिल होती हैं।

3. करों से प्राप्त आय

नकदी लेखा आधार में कर संबंधी आयों को नकदी आधार पर उस वर्ष में रिकार्ड किया जाता है जिस वर्ष उन्हें प्राप्त किया जाता है। प्रतिदायों (रिफण्ड्स) को उस वर्ष आय से कम किया जाता है जिस वर्ष उन्हें संदत्त किया जाता है। उपार्जन (एक्रुअल) लेखा में कर प्राप्तियों और प्रतिदायों को सामान्यतः उस वर्ष में रिकार्ड किया जाता है जिस वर्ष में कर देय योग्य होते हैं। तदनुसार, करों के लिए प्राप्य लेखा शीर्ष खाता और कर प्रतिदायों (रिफण्ड्स) जो कि करदाताओं को देय है, के लिए देय लेखा शीर्ष खाते खोले जाते हैं।

उपार्जन (एक्रुअल) लेखा के लाभ

सभी हितधारियों को सम्पूर्ण जानकारी की उपलब्धता उन्हें जन संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है। उपार्जन (एक्रुअल) लेखांकन से स्थानीय निकायों की अल्पकालिक और दीर्घकालिक वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में भी सक्षमता सुधारने में सहायता करता है।

- स्थानीय निकाय का तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) इसकी आस्तियों और देनदारियों की एक उचित या विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
- वार्षिक बजटीय अतिशेष वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक घटनाओं के प्रभाव को प्रतिबिम्बित करता है। विशेषकर, रिकार्ड की गई कर संबंधी आयों में वर्ष-दर-वर्ष हुए परिवर्तनों में, कर आधार और कर संबंधी दरों में वर्ष-दर-वर्ष हुए परिवर्तनों को सही प्रतिबिम्बित करती है क्योंकि इन परिवर्तनों पर कर संग्रहण में आयी कमी और प्रतिदायों (रिफण्ड्स) के भुगतान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

- वार्षिक बजटीय अतिशेष वित्त वर्ष के दौरान स्थानीय निकाय के निर्णयों के प्रभाव को दर्शाता है। विशेषकर, उन निर्णयों के जिनके परिणामस्वरूप इसकी देनदारियों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि प्राप्त संसाधनों को उसी वर्ष रिकार्ड किया जाता है जिस वर्ष आर्थिक घटना घटित होती है। नकदी लेखा के अंतर्गत कुछ निर्णयों की पूर्ण लागत को स्थानीय निकाय के वित्तीय विवरणों में तब तक नहीं दर्शाया जाता जब तक किए जाने वाले सभी नकद भुगतानों का भुगतान नहीं कर दिया जाता जिनका कई वर्षों बाद नकद भुगतान किया गया है।

आशा है कि उपार्जन (एक्रुअल) लेखा का प्रयोग स्थानीय निकाय के प्रबंधकों और निर्णय लेने वाले व्यक्तियों को संसाधनों के आवंटन के कार्यों का प्रबंधन करने और जोखिम निर्धारण संबंधी बेहतर निर्णयों को लेने में भी मदद करेगा।

- चूंकि सभी आस्तियों (वित्तीय आस्तियां और गैर-वित्तीय आस्तियां) को स्थानीय निकाय के वित्तीय लेखाओं में रिकार्ड किया जाता है, प्रबंधक अपने नियंत्रण में आने वाली आस्तियों के प्रबंधन के बारे में अधिक सतर्क हो जाएंगे और अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं, प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) संबंधी नीतियों, अनावश्यक या अतिरिक्त आस्तियों की पहचान और उनके निपटान, चोरी या टूट-फूट द्वारा हानि और सेवाओं के प्रदान किए जाने पर आस्तियों के ऊपर पूर्ण प्रभाव जैसे मुद्दों पर उचित ध्यान देंगे।
- चूंकि उपार्जन (एक्रुअल) लेखांकन मौजूदा और संभाव्य देनदारियों की पहचान करती है इसलिए प्रबंधक अपने नियंत्रण में आने वाली देनदारियों के प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान देंगे और उन देनदारियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व और भावी संसाधनों पर मौजूदा देनदारियों के प्रभाव को पहचानने सहित उनके (देनदारियों) प्रबंधन हेतु योजनाओं को विकसित करने की आवश्यकता के प्रति सजग होंगे।
- चूंकि प्रचालन संबंधी सभी लागतों को स्थानीय निकाय के लेखाओं में रिकार्ड किया जाता है, प्रबंधकों को निकाय के वित्तीय निष्पादन (सभी लागतों और आयों) की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ऐसा करने से आंतरिक परिदान (इन-हाउस डिलिवरी) बनाम सेवाओं को ठेके पर बाहर देने में लागत की प्रभावशीलता के मूल्यांकन, लागत-वसूली नीति की सटीकता या प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य अभिकरणों से वसूली जाने वाली राशि जैसे निर्णय लेते समय सभी लागतों पर विचार करने में उनकी मदद करेगा।
- स्थानीय निकाय अपनी आस्तियों की बेहतर गतिशीलता से प्रबन्धन और प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ऋण लेने में सक्षम होंगे।

स्थानीय निकायों में उपार्जन (एक्रुअल) लेखा प्रणाली : कुछ मिथक

स्थानीय निकायों के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच उपार्जन (एक्रुअल) लेखा प्रणाली के संबंध में मिथक (गलत फहमियां) हैं। मिथक (गलत फहमियां) बनाम वास्तविक तथ्य नीचे दिए गए हैं :

मिथक	वास्तविकता
नकदी लेखा समय की कसौटी पर खरा उतरा है इसलिए उपार्जन (एक्रुअल) लेखा प्रणाली की जरूरत नहीं है।	लेखा का नकदी आधार भिन्न वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संभवतः नकदी प्राप्तियाँ और नकदी भुगतान का समय राजस्वों के अर्जन या व्यय के वहन होने से मेल न खाए। इसके अतिरिक्त, लेखा के नकदी आधार पर आधारित निष्पादन का मापन नकद प्राप्तियों या भुगतानों के समय में भिन्नता का लाभ लेते हुए हेरा-फेरी के प्रति संवेदनशील है।
उपार्जन (एक्रुअल) लेखा प्रणाली चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स के व्यवसाय को बढ़ावा देती है।	स्थानीय निकाय, राज्य के स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों और/या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण द्वारा लेखा परीक्षा के आधीन है। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स लेखांकन मुद्दों में ही सहायता करते हैं।
उपार्जन (एक्रुअल) लेखांकन प्रणाली में कम्प्यूटरों और महँगे लेखा साफ्टवेयरों में भारी निवेश की आवश्यकता होती है।	स्थानीय निकायों में उच्च स्तरीय कम्प्यूटर प्रणालियों की आवश्यकता नहीं होती। निकाय के आकार और कार्य की मात्रा के आधार पर कम्प्यूटरों की लागत 1,00,000 रु० से लेकर 2,00,000 रु० के बीच होगी। 90% से अधिक स्थानीय निकायों को कम्प्यूटर हार्डवेयर पर 3,00,000 रु० से कम और साँफ्टवेयर पैकजों पर 50,000 रु० से कम लागत की आवश्यकता होगी।
उपार्जन (एक्रुअल) लेखा के कारण कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।	अधिकतर स्थानीय निकायों में लेखा कर्मचारियों की कमी है। कर्मचारियों की आवश्यकता लगभग समान रहेगी।
दोहरी प्रविष्टि उपार्जन (एक्रुअल) लेखा प्रणाली का अर्थ है देहरा कार्यभार।	विद्यमान नकद लेखा प्रणाली में भी स्थानीय निकाय दो-तरफा पड़ताल के लिए रिकार्डों का दूसरा सेट तैयार रखते हैं, यद्यपि

	<p>यह रिकार्ड असंबद्ध होते हैं। दोहरी प्रविष्टि उपार्जन (एक्रुअल) लेखा प्रणाली में, रिकार्डों का दूसरा सेट लेखा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन जाता है। हस्तलिखित रूप में भी दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली कार्यभार को दुगना नहीं करती। इसका कम्प्यूटीकृत रूप कार्यभार को कम करता है और उसे सरल बनाता है।</p>
<p>उपार्जन (एक्रुअल) लेखा को अपनाने का अर्थ है कि स्थानीय निकाय बाजार से ऋण लेने की स्थिति में हैं।</p>	<p>बाजार से ऋण लेना स्थानीय निकाय की सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति और इसकी बैंक-योग्य परियोजनाओं पर निर्भर करता है। मात्र लेखा सुधार ही बाजार से ऋण लेने में मदद नहीं कर सकते। लेखा संबंधी सुधार इसके वित्तीय परिणामों को ऐसी भाषा या प्रारूप में परिवर्तित करने में मदद करते हैं जिससे बाजार अवगत है और जिसे वह सरलता से समझते हैं। लेखा संबंधी सुधार, स्थानीय निकाय द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों को ज्यादा विश्वसनीयता देता है।</p>
<p>उपार्जन (एक्रुअल) लेखा स्थानीय निकाय की बेहतर वित्तीय स्थिति दर्शाता है।</p>	<p>लेखा सुधार जादुई छड़ी नहीं हैं और हो सकता है कि इससे स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति ना सुधरे। उपार्जन (एक्रुअल) लेखा उपयुक्त वित्तीय निर्णय लेने के लिए अधिक गुणवत्ता वाले एवं विश्वसनीय आँकड़ें उपलब्ध कराकर स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुधार सकता है।</p>

स्थानीय निकायों के लिए लेखा मानक समिति के बारे में

उच्च गुणवत्ता वाले वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के एकल सेट की आवश्यकता को पहचानते हुए, अधिक से अधिक स्थानीय निकाय लेखा के नकदी आधार को छोड़कर उपार्जन (एक्रुअल) आधार को अपना रहे हैं। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (आई. सी. ए. आई) की केन्द्रीय परिषद ने स्थानीय निकायों के लिए उपार्जन (एक्रुअल) आधार पर लेखा मानकों के निर्माण के मुख्य उद्देश्य से मार्च 2005 में स्थानीय निकायों के लिए लेखा मानक स्वतंत्र समिति (सी. ए. एस. एल. बी.) का गठन किया है।

सी. ए. एस. एल. बी. की संरचना काफी व्यापक है और मानकों को निर्धारित करने की प्रक्रिया में सभी हितधारक समूहों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। आई. सी. ए. आई. के केन्द्रीय परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त, सी. ए. एस. एल. बी. में भारत सरकार का शहरी विकास मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय, प्रमुख स्थानीय निकायों के निदेशालयों, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभागों के निदेशालयों, शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि और आई. सी. ए. आई. द्वारा सहयोजित प्रतिष्ठित व्यवसायी शामिल हैं।

स्थानीय निकायों के लिए लेखा मानकों को विकसित करने के अतिरिक्त, समिति स्थानीय निकायों की लेखा संबंधी कार्यप्रणाली और पद्धतियों में सुधार को सुविधाजनक बनाने हेतु भी कदम उठाती है और उपार्जन (एक्रुअल) लेखा को अपनाने में और स्थानीय निकायों के लिए लेखा मानकों की प्रस्तावना में निर्धारित लेखा मानकों के अनुप्रयोग में स्थानीय निकायों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में उनसे (स्थानीय निकायों से) प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है।

स्थानीय निकायों के लिए लेखा मानकों को विकसित करते समय, सी. ए. एस. एल. बी. अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मानक बोर्ड (आई. पी. एस. ए. एस. बी.) द्वारा तैयार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मानक (आई. पी. एस. ए. एस.) के साथ उचित विचार-विमर्श करती है और वैश्विक समरसता को सुविधाजनक बनाने के लिए, जहाँ तक संभव हो, उन्हें समन्वित करने का प्रयास करती है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) के बारे में

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई. सी. ए. आई.) भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के व्यवसाय के विनियमन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 की अधिनियम संख्या XXXVIII) के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। अपने अस्तित्व के करीब छः दशकों के दौरान आई. सी. ए. आई. ने शिक्षा, व्यावसायिक विकास, लेखा, लेखापरीक्षा और आचार संबंधी मानकों के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए, न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी, एक अग्रणी लेखा निकाय के रूप में पहचान बनायी है। आई. सी. ए. आई. अब पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लेखाकन निकाय है।

मुम्बई, चैन्नई, कानपुर, कोलकाता व नई दिल्ली में पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ आई. सी. ए. आई. का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और देश भर में इसकी 117 शाखाएँ हैं। इसके अतिरिक्त, इसने भारत के बाहर 19 शाखाएँ एवम् दुबई में एक कार्यालय भी स्थापित किया है।

आई. सी. ए. आई. के मामलों का प्रबंधन केन्द्रीय परिषद द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय परिषद में 40 सदस्य होते हैं जिनमें से 32 को सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है और शेष आठ सदस्यों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुसार अध्यक्ष, परिषद का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी है। आई. सी. ए. आई. के सचिवालय का नेतृत्व सचिव करता है जो कि आई. सी. ए. आई. के कार्यपालक प्रमुख के रूप में इस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी हैं। आई. सी. ए. आई. के क्रियाकलापों को मोटे तौर पर चार भागों, तकनीकी निदेशालय, सतत व्यवसायिक शिक्षा निदेशालय, बोर्ड ऑफ स्टडीज (अध्ययन परिषद) और प्रशासन में बाँटा जा सकता है और प्रत्येक प्रभाग का एक अलग मुखिया है। आई. सी. ए. आई. के अन्य प्रमुख प्रभाग हैं : परीक्षा प्रभाग, अनुशासनात्मक प्रभाग, कानूनी प्रभाग, सदस्य एवम् छात्र सेवाएँ, अंतर्राष्ट्रीय मामले, अनुसंधान, आदि। आई. सी. ए. आई. ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत आई. सी. ए. आई. लेखांकन अनुसंधान फाउन्डेशन की स्थापना भी की है।